



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 अक्तूबर, 1992/11 आश्विन, 1914

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 अक्तूबर, 1992 -

संख्या गृह (ए) ए (9) 24/92.—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया है कि 21 मार्च, 1992 को ऊना में हुए मैडी मेले में श्रद्धालुओं तथा वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल में झड़प हुई थी,

और यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस बल ने अभिकथित रूप में अपन प्राधिकार का दुरुपयोग किया, श्रद्धालुओं की पिटाई की और अनुचित रूप से धार्मिक स्थल की पवित्रता का अतिक्रमण करने का प्रयास किया,

और जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने इस घटना की सच्चाई जानने के लिए मैजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया था,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सार्वजनिक हित की ध्यान में रखते हुए, यह समीचीन होगा कि उक्त घटना जोकि महत्वपूर्ण मामला है की जांच के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाए,

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इस सरकार की पत्र संख्या गृह (ए) ए (9) 24/92, तारीख 23-9-1992 द्वारा माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश से उपर्युक्त घटना की सच्चाई जानने के लिए जांच आयोग के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए उनकी सहमति मांगी थी,

और माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के आयुक्त एवं सचिव ने पत्र संख्या 5 (इ) 5-2/92-लोक (15-ए), दिनांक 25 सितम्बर, 1992 द्वारा प्रस्तावित जांच करने के लिए माननीय लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश को सहमति दे दी गई है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 15-ए के अधीन, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 18-7-92 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना संख्या गृह (ए) ए (9) 24/92, तारीख 17 जुलाई, 1992 का अधिक्रमण करते हुए लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश उपर्युक्त घटना से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों पर जांच करने और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर इस निमित्त अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं:—

- (1) घटना स्थल पर, घटना घटित होने से पूर्व और पश्चात् क्या स्थिति थी ?
- (2) क्या तथ्य और परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण अभिसूचना मारपीट, पत्थर फेंकने और आगजनी इत्यादि की गई और वहाँ मौके पर तत्काल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले तन्त्र की क्या प्रतिक्रियाएँ थीं और अनुक्रियाएँ भी ?
- (3) क्या यह सत्य है कि कुछ पुलिस कर्मियों ने अपने आचरण के विरुद्ध कार्य करते हुए धार्मिक स्थान की पवित्रता का अतिक्रमण किया ?
- (4) क्या यह सत्य है कि वहाँ पर चल रहे अखण्ड पाठ में उन्होंने विघन डाला और ग्रन्थियों से मारपीट की ?
- (5) यदि कोई सुरक्षा कर्मी धार्मिक स्थान के ग्रन्थी की सुरक्षा हेतु तनात थे, तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई ?
- (6) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ? और
- (7) कोई अन्य विषय जो आयोग की राय में उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में तथ्यों को अभिनिश्चित करने से सुसंगत हो।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की आगे यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मायले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबन्धों को आयोग के लिए लागू किया जाए और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) में उल्लिखित उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

जांच आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा और यह ऐसे स्थानों की यात्रा (निरीक्षण) भी कर सकेगा जो जांच को आगे बढ़ाने में सहायक हों।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

[*Authorised English Text of Notification No. Home(A) 4 (9) 24/92, dated 3-10-1992 under Articles 345 of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd October, 1992

No Home (A) A (9)-24/92.—Whereas, it has been reported to the Himachal Pradesh Government that a clash between the devotees and the police force deployed for maintenance of law and order at Mairi fair at Una took place on March 21, 1992 ;

And whereas, it has been alleged that the police force allegedly abused their authority, beat up the devotees and unduly tried to violate the sanctity of the religious place ;

And whereas, the District Magistrate, Una had ordered a magisterial enquiry to get at the truth behind this incident ;

And whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to enquire into the aforesaid occurrence which is a matter of importance ;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh has approached the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh *vide* this Government letter No. Home (A)A (9)24/92, dated 23rd September, 1992 to have his consent for appointment as the Commission of Inquiry to enquire into the truth behind the aforesaid incident ;

And whereas the Commissioner-cum-Secretary to Lokayukta, Himachal Pradesh has conveyed the consent of the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh for holding the proposed enquiry *vide* letter No. 5(E)5-2/92 Loka (15-A), dated 25-9-92.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, in consultation with the Lokayukta, Himachal Pradesh under section 15-A of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) and in supersession of this Government Notification No. Home (A)A (9)24/92, dated 17th July, 1992 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated 18-7-1992, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint the Hon'ble Lokayukta, Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry and to enquire into the report on the following matters in relation to the aforementioned occurrence within a period of 6 months from the date of publication of this notification:—

- (1) what was the situation prevailing on the spot before and after the incident ?
- (2) what were the facts and circumstances leading to the alleged beatings, stone throwing and arson etc. and what were the reactions and responses of the law and order enforcement machinery deployed at site ?
- (3) whether it is a fact that some of the police personnel by virtue of their conduct violated the sanctity of the religious place ?
- (4) whether it is a fact that they disturbed the recitation of the Akhand Path and beat the Granthis ?

- (5) what was the role played by the security guards, if any, attached to the Granthi of the religious place ?
- (6) to recommend steps necessary for the prevention of recurrence of such incidents in future ? and
- (7) any other matter in the opinion of the Commission relevant to the ascertaining of facts relating to the aforesaid occurrence ?

Further the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the enquiry to be conducted and circumstances of the case the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952 should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 5 of the aforesaid Act is pleased to direct that the provisions mentioned in sub-section (2), (3), (4) and (5) of section 5 shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at Shimla and may also visit such places as may be necessary in the furtherance of the Inquiry.

By order,

M. S. MUKHERJEE,
Chief Secretary,